<u>समयबद्ध</u>

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-09/2022/740/सैंतालिस–का-1-2022-13(3)/2022
लखनऊ:: दिनांक 25 जुलाई, 2022

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
<u>उत्तर प्रदेश शासन।</u>

कृपया रिट याचिका संख्या-2555/2022 रिट-ए प्रकाश चन्द्र अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07 मई 2022 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा योजित विशेष अपील संख्या-97/2022 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-22.07.2022 को पारित किये गए आदेश का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

..... At this stage, we are only examining the issue regarding training part of Enquiry Officers in the State. Learned Single Judge vide order dated May 7, 2022 issued direction that no Enquiry Officer in future shall be appointed for departmental inquiry, who has not received training from the Judicial Training & Research Institute (hereinafter referred to as "JTRI"). We find 2 Special Appeal Defective No.97 of 2022 that this sweeping direction will withhold number of inquires, which are pending in the different departments in the State keeping in view the infrastructure available in the JTRI. For conducting such inquiries, the importance of training to the officers, who have to hold the departmental inquiry, may not be lost sight of keeping in view the repeated violation of principles of natural justice and the rules governing such inquiries.

5. In the affidavit filed today, certain communications have been annexed and figures have been provided regarding training programs conducted after passing of the aforesaid order and from April 1, 2022 onwards. It is claimed that departmental inquiry is one of the subject in the training programme of the Officers but what we find prima facie is that the training being imparted is not yielding the results as required, as still the rules and principles of natural justice are found to be violated. The training programme for such Officers has to be more robust and specialised, for which the State is directed to place before the Court a comprehensive plan.

6. As the sweeping directions issued by the learned Signle Judge will withhold all the departmental inquiries, we stay those directions to the extent - 'that no Officer in future shall be appointed for departmental inquiry unless he has received training from JTRI'. However, we expect that in the pending inquiries, the Officers holding such inquiries shall be sensitised without any delay and further the training programs of the Officers shall be regular exercise.

2- मा० न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के क्रम में मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि अपने विभाग में प्रचलित ऐसी विभागीय कार्यवाहियां, जिनमें जाँच पूर्ण होने के उपरान्त जाँच आख्यायें अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु लंबित हैं, की सूचना कार्मिक अनुभाग-1 को **दिनांक-27.07.2022** तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें | (क्षेत्रीय स्तर से अथवा एक ही विभाग के भिन्न-भिन्न अनुभाग के स्तर से प्राप्त सूचनाये अनुश्रवण हेतु ग्रहण/संकलित नहीं की जायेगी)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपर्युक्त सूचना कार्मिक अनुभाग-1 की ई-मेल आई०डी० karmiksection1@gmail.com पर भी प्रेषित की जा सकती है |

राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव

संख्या-09/2022/740/सैंतालिस–का-1-2022-13(3)/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव,सचिवालय प्रशासन विभाग
2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग।

जय प्रकाश तिवारी
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।